भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1523
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2021

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

1523. श्री विष्णु दत्त शर्मा, श्री जुगल किशोर शर्मा एवं श्रीमती गीता कोडा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देशभर के प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इसके अंतर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त मिशन पीपीपी पद्धति पर आधारित है; और
(ङ) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ सरकार द्वारा उक्त मिशन के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया है और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क), (ख) और (ग): राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन के तहत वर्ष 2022 तक देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैण्ड अभिगम उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो नेटवर्क और सैटेलाइट सहित अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस मिशन का लक्ष्य गांवों में सभी को ब्रॉडबैण्ड अवसंरचना के लाभ प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख विकासात्मक संस्थाओं को उच्च गति ब्रॉडबैण्ड उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से सरकार द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रूपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ): भारतनेट परियोजना जो कि इस मिशन का एक प्रमुख घटक है, अपने दूसरे चरण में पीपीपी माध्यम द्वारा आंशिक रूप से और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू)-आधारित मॉडल, राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र-आधारित मॉडल जैसे विभिन्न मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को खुली निविदा के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

*****